पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 2721

में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.-453

==========

विचार के लिए विषयः क्या अपीलार्थी बिहार किरायेदारी अधिनियम, 1885 की धारा 48ई के तहत बटाईदार होने के अपने दावे का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा है और क्या हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली अपील में कोई योग्यता है

बिहार किरायेदारी अधिनियम की धारा 48डी-मौजा सुपौली थाना नं. 271, भवानीपुर, पूर्णिया-डी. सी. एल. आर. ने एक आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को बटाईदार घोषित किया-कलेक्टर के समक्ष प्रत्यर्थी की अपील खारिज-डी. सी. एल. आर. और कलेक्टर के आदेश से व्यथित प्रत्यर्थी ने बिहार भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष आदेश को चुनौती दी-डी. सी. एल. आर. और कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया-अपीलार्थी ने रिट याचिका को प्राथमिकता दी-जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था-अपीलार्थी ने इस अदालत के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी जिसे खारिज कर दिया गया था-बिहार किरायेदारी अधिनियम, 1885 की धारा 48ई के तहत जुगेश्वर मंडल द्वारा दाखिल आवेदन खारिज कर दिया गया-अपीलार्थी बटाईदारी समझौता स्थापित करने में विफल रहा-क्या याचिकाकर्ता बिहार किरायेदारी अधिनियम, 1885 की धारा 48ई के तहत बटाईदार होने के अपने दावे का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा

अभिनिर्धारित: अपीलार्थी ने दावा किया कि उसने नियमित रूप से उपज का हिस्सा देते हुए बटाईदारी की, क्योंकि रसीद की कोई प्रथा नहीं थी, उसने दावा किया कि उसके पास बटाईदारी की रसीद नहीं थी, डी. सी. एल. आर. ने स्थानीय निरीक्षण के आधार पर उसे बटाईदार घोषित कर दिया, डी. सी. एल. आर. ने स्पष्ट रूप से आदेश पारित करने में गलती की क्योंकि कोई विरासत अधिकार स्थापित नहीं किया गया था, कलेक्टर ने भी केवल डी. सी. एल. आर. आदेश की पुष्टि करके अपील में गलती

की। डी. सी. एल. आर. के आदेश से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने इस आधार पर बटाईदार नहीं माना है कि उसे ऐसे अधिकार विरासत में मिले हैं। किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि याचिकाकर्ता के पिता या उनके दादा ने बिहार किरायेदारी अधिनियम की धारा 48 डी के तहत अधिभोग का अधिकार प्राप्त कर लिया है। बटाईदारी एक ऐसा समझौता है जो तब तक चलता है जब तक कि उक्त बटाईदार उक्त भूमि पर खेती करता है और वह भूमि के स्वामी को भूमि के लिए उपज का किराया देता है।

अदालत ने यह भी कहा है कि रैयत बनने के लिए, रैयत और रैयत के तहत समझौते का कुछ तत्व होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को रैयत के तहत नहीं ठहराया जा सकता है यदि उसने बिना किसी समझौते के भूमि पर कब्जा कर लिया है। यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद मकान मालिक के साथ बटाईदारी समझौता किया था, साथ ही सुलह के प्रयासों का भी पूर्ण अभाव था। यह भी उल्लेख करना उचित है कि अपीलकर्ता के पिता का आवेदन पहले बिहार किरायेदारी अधिनियम की धारा 48ई के तहत खारिज कर दिया गया है। [पदारथ चौधरी बनाम मोस्ट जोगतिया (1987 बी. एल. जे. 636), श्रीकिशुन बनाम हरिहर (आई. एल. आर. 27 पटना 194), बीबी जलोसन बनाम। भुलई बैठा (1981 बी. बी. सी. जे. 466)] [कंडिका 9]

बिहार किरायेदारी अधिनियम की धारा 48डी-**बिहार किरायेदारी अधिनियम, 1885 की धारा 48ई के तहत जुगेश्वर मंडल के द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया गया**-अपीलार्थी ने **बिहार किरायेदारी अधिनियम, 1885 की धारा 48ई** के तहत अलग आवेदन दायर किया **जिसे खारिज कर दिया गया** -

डी. सी. एल. आर. ने आदेश पारित करने में स्पष्ट रूप से गलती की, कलेक्टर ने केवल डी. सी. एल. आर. आदेश की पुष्टि करते हुए अपील में भी गलती की-बटाईदारी अधिकार तब तक विरासत में नहीं लिया जा सकता जब तक कि कोई रैयत बिहार किरायेदारी अधिनियम की धारा 48 डी के अर्थ के भीतर अधिभोग के अधिकार को प्राप्त नहीं कर लेता, यह भी उल्लेख करना उचित है कि अपीलकर्ता के पिता ने एक समान दावा किया था जिसे पहले उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 2721

में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.-453

==========

अशोक मंडल, पुत्र- स्वर्गीय कमलेश्वरी मंडल @ जागेश्वर मंडल गांव- ब्रह्म ज्ञानी, थाना- भवानीपुर, जिला-पूर्णिया

.....अपीलार्थी/अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. जिला कलेक्टर पूर्णिया
3. उप-कलेक्टर भूमि सुधार, धमदाहा, जिला-पूर्णिया
4. आंचल अधिकारी भवानीपुर थाना- भवानीपुर, जिला-पूर्णिया
5. हेमंत कुमार सिंह @हेमंत कुमार सिन्हा पुत्र नरेंद्र कुमार सिंह निवासी ग्राम-कपसौना, थाना- सबौर, जिला-भागलपुर, वर्तमान में ग्राम-ब्रह्म ज्ञानी, थाना भवानीपुर, जिला-पूर्णिया के निवासी निवासी हैं।

.....उत्तरदाता/उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी/अपीलार्थीगण के लिएः श्री योगेंद्र कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री मो. खुर्शीद आलम (एएजी)

श्री समीर अली खान, अधिवक्ता

श्री बिनय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रॉय

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायाधीश श्री राजीव रॉय)

तिथीः 11-01-2024

पक्षों को सुना।

2. अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 2721 में दिनांक 27.02.2019 के आदेश से उत्पन्न होती है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी-याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया, प्रतिवादी संख्या-5 का 'बटाईदार' होने के अपने दावों को बिहार किरायेदारी अधिनियम, 1885 (अब से संक्षिप्त में, 'अधिनियम') की धारा 48ई के तहत भी स्थापित करने में विफल रहा। रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।

3. मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः

4. विवाद खाता नं. 226, प्लॉट नं.46 (भाग) (क्षेत्रफल 2.88 एकड़) मौज़ा-सुपौली, थाना नं.271, पूर्णिया जिले में भवानीपुर (इसके बाद प्रश्नगत भूमि के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत भूमि के एक टुकड़े से संबंधित है।

5. जुगेश्वर मंडल नामक एक व्यक्ति ने 1993 के वाद सं.35 के माध्यम से प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 48ई के तहत आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसे रद्द कर दिया गया।

6. वर्ष 2003 में, अपीलार्थी ने 'बी. टी. अधिनियम' की धारा 48ई के तहत एक और याचिका दायर की, जिसने 2003 का मामला सं. 23 को उद्भूत किया। उक्त याचिका में, उन्होंने खुद को कमलेश्वरी मंडल का पुत्र होने का दावा करते हुए कहा कि उन्होंने इसे अपने दादा, बिगन मंडल से 'बटाईदारी' के रूप में लिया है। याचिकाकर्ता के दादा की वर्ष 1988 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता 'बटाईदारी' कर रहे थे और 04.01.2002 को उनकी मृत्यु के बाद, अपीलार्थी ने बटाईदारी को अपनाया, नियमित रुप से उत्पाद में हिस्सा दिया। चूंकि रसीद देने की कोई प्रथा नहीं थी, इसलिए यह दावा किया जाता था कि उनके पास 'बटाईदारी' की रसीद नहीं थी।

7. डी. सी. एल. आर. ने दिनांक 28.04.2005 के एक आदेश के माध्यम से स्थानीय निरीक्षण प्रभावी 26.04.2003 के आधार पर 26.04.2003 के प्रभाव से, जिस तिथि को भू-स्वामियों ने उसे भूमि खाली करने की सूचना दी, उसे बटाईदार घोषित किया। प्रत्यर्थी सं.5 ने समाहर्ता, पूर्णियां के समक्ष 2005 का राजस्व अपील सं.-109 में जिसे 08.02.2009 को रद्द कर दिया गया।

8. व्यथित होकर, प्रत्यर्थी सं.- ने 2011 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार सं.- 18602 को प्राथमिकता दी एवं न्यायालय ने दिनांक 30.08.2016 के आदेश के माध्यम से उन्हें बिहार भूमि न्यायाधिकरण (इसके पश्चात संक्षिप्त में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष आदेश को चुनौती देने की मंजूरी दी। इसके बाद 2017 का बी. एल. टी. मामला संख्या 481 आया, जिसमें पक्षों को सुनने के बाद, डी. सी. एल. आर. के साथ समाहर्ता द्वारा भी पारित आदेशों को दिनांक 06.04.2018 के एक आदेश के माध्यम से अलग कर दिया गया।

9. पीड़ित होकर, अपीलार्थी ने रिट याचिका को प्राथमिकता दी। इस मामले की सुनवाई विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई थी और दिनांकित 27.02.2019 के एक आदेश के माध्यम से, इसे खारिज कर दिया गया था। आदेश के पैरा 13 से 19 को शामिल करना प्रासंगिक है जो इस प्रकार हैः

*"13. उप-कलेक्टर भूमि सुधार के दिनांक 28.04.2015 के आदेश से जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि उन्होंने याचिकाकर्ता को इस आधार पर बटाईदार नहीं माना है कि उसे अपने पिता की मृत्यु के परिणामस्वरूप ऐसा कोई अधिकार विरासत में मिला है। उप-कलेक्टर भूमि सुधार या कलेक्टर द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि याचिकाकर्ता के पिता ने अधिनियम की धारा 48डी के तहत रैयती अधिकार प्राप्त किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह समर्पण कि याचिकाकर्ता को अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त 2002 में बटाईदार के रूप में कोई अधिकार विरासत में मिला, पर बिल्कुल भी विचार नही किया जा सकता है। **बलभद्र प्रसाद सिंह** (ऊपर) के मामले में खंड पीठ के फैसले पर याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील ने भरोसा रखा है। **बलभद्र प्रसाद सिंह** (ऊपर) के मामले में, खंड पीठ ने पैराग्राफ 8 में कहा है कि 'रैयत के तहत अधिभोग के अधिकार उत्तराधिकार शब्दों के कारण विरासत में मिलेंगे, जो अधिनियम की धारा 48डी में हुआ था जैसा कि इसके संशोधन से पहले था। किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि याचिकाकर्ता के पिता या उनके दादा ने अधिनियम की धारा 48डी के अर्थ के भीतर अधिभोग का अधिकार प्राप्त कर लिया था। **बलभद्र प्रसाद सिंह** (ऊपर) के मामले में उक्त निर्णय की कंडिका 8 प्रासंगिक है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः*

"8. इस न्यायालय के ऐसे निर्णय हैं जिन्होंने उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के प्रभाव पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रैयत के तहत स्वामित्व के अधिकार विरासत में मिलेंगे लेकिन हस्तांतरणीय नहीं होंगे। यह 'का

उत्तराधिकार' शब्दों के कारण हैं जो अधिनियम की धारा 48 डी में हुआ जैसा कि यह इसके संशोधन से पहले था। उदाहरण के रुप में हम पदारथ चौधरी बनाम मोस्मात जोगिता के मामले के निर्णय का जिक्र कर सकते है (1987 बी. एल. जे. 636 जिसमें श्रीकिशुन बनाम हरिहर (आई. एल. आर. 27 पटना 194) के मामले में इस न्यायालय के खंड पीठ के निर्णय एवं बीबी जलुसन बनाम भुलाई बैठा (1981 बी. बी. सी. जे. 466) के मामले में एकल न्यायाधीश के निर्णय पर भरोसा किया गया था, हम निर्णयों के कंडिका-10 में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 12 वर्ष से अधिक समय तक अपने कब्जे के निरंतर अधिकार के कारण रैयत के तहत उत्तराधिकार आदि का अधिकार हो सकता है, लेकिन स्थानांतरण का अधिकार नही हो सकता है। देहल महतो बनाम नाथूनी राम मारवाड़ी 2006 (2) पी. एल. जे. आर. 642 के मामले में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले में भी ऐसा ही विचार रखा गया है। ”

*14. इसी तरह का विचार **सुखदेव पंडित** (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ द्वारा लिया गया है, जिसकी कंडिका 12 इस प्रकार हैः*

“12. यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस दावे को सत्यापित करने के लिए कि नोटिस के बावजूद निजी प्रत्यर्थी बोर्ड के समक्ष उपस्थित नही हुए, हमने समाहर्ता, बाँका से मूल अभिलेख की माँग की थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि बोर्ड के समक्ष कार्यवाही के लिए निजी उत्तरदाताओं को नोटिस तामिल की गई थी या नही। हम अभिलेखों से यह नहीं पाते हैं कि क्या नोटिस वास्तव में निजी उत्तरदाताओं को भेजे गए थे या उन्हें दिए गए थे। निजी उत्तरदाताओं ने दलील दी है कि उन्हें बोर्ड के समक्ष कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ”

*15. **सुखदेव पंडित** (ऊपर) के मामले में, खंड पीठ ने स्पष्ट रुप से यह अभिनिर्धारित किया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि बटाईदारी प्रधानतः रैयत एवं रैयत के तहत (बटाईदार) के मध्य एक समझौता है, जो समझौता तब तक कायम रहता है, जब तक उक्त बटाईदार अपने कब्जे की उक्त भूमि पर खेती करता है एवं वह उसके द्वारा अधिग्रहित भूमि पर उत्पाद किराए का भू-स्वामी को भुगतान करता है। **कार्तिक सिंह और एक अन्य** के मामले में (उपर्युक्त) में भी इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि रैयत के अधीन बनने के लिए रैयत और रैयत के तहत के बीच समझौते या अनुबंध का कुछ तत्व होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को रैयत के अधीन नहीं ठहराया जा सकता है यदि उसने ऐसे किसी समझौते के बिना भूमि पर कब्जा कर लिया है।*

16. कानून के प्रस्तावों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान निर्णय के लिए, मैं दोहराता हूं कि याचिकाकर्ता का मामला कि वह वर्ष 2002 में अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद रैयत के तहत खेती कर रहा था, यह नहीं कहा जा सकता है कि उप कलेक्टर भूमि सुधार और कलेक्टर, पूर्णिया द्वारा स्वीकार किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता को उनके द्वारा 26.04.2003 से प्रभावी बटाईदार माना गया है। भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पिता उनकी मृत्यु की तारीख को प्रतिवादी संख्या 5 के बटाईदार थे, यदि कोई बटाईदारी समझौता था, तो उसकी मृत्यु की तारीख को उसका बल समाप्त हो गया। उप समाहर्ता भूमि सुधार और समाहर्ता, पूर्णिया के आदेश में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री इंगित नहीं की गई है कि याचिकाकर्ता ने भू-स्वामी (प्रतिवादी संख्या 5) के साथ बटाईदारी समझौता किया है। उपरोक्त के अलावा, मुझे न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारण में कोई अवैधता नहीं मिलती है कि सुलह के प्रयासों का पूर्ण अभाव था, जिसने उप-कलेक्टर भूमि सुधारों द्वारा पारित आदेश को भी अवैध बना दिया।

17. प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने, मेरी राय में, सही प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 48ई के तहत इस तरह के अधिकार की मांग करने वाले आवेदन में अपने दावे के आधार पर, प्रथम दृष्टया, प्रत्यर्थी संख्या 5 का बटाईदार होने के अपने वास्तविक दावे को भी स्थापित करने में विफल रहा है।

18. उपरोक्त कारणों से, न्यायाधिकरण के विवादित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

19. यह आवेदन तदनुसार रद्द किया जाता है। ”

10. व्यथित होकर, वर्तमान अपील।

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिका को गलत निष्कर्ष पर खारिज कर दिया गया था कि वह अपने पिता की मृत्यु के समय केवल सात साल का था और इस तरह 'बटाईदारी' नहीं कर सकता था। इसके विपरीत, वर्ष 2002 में वे उनतीस वर्ष के थे और इस आशय का शपथ पत्र भी दिया गया था।

12. यह उनका आगे का निवेदन है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मतदाता सूची पर निर्भरता रखी है जिसे प्रामाणिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिवादी नं। 5 'अधिनियम' के तहत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष वैधानिक अपील का मार्ग अपनाना चाहिए था, जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था।

13. प्रतिवादी सं. 2 से 4 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। 2 से 4 जो रिकॉर्ड में है। पैराग्राफ 5 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता जुगेश्वर मंडल का पुत्र है जिसका आवेदन 'अधिनियम' की धारा 48ई के तहत पहले हटा दिया गया था। अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि जुगेश्वर मंडल उसके पिता कमलेश्वरी मंडल का उपनाम है और इस प्रकार, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि धारा 48ई के

तहत उक्त कार्यवाही में। ''अधिनियम' को पहले हटा दिया गया था। उस पृष्ठभूमि में और यह भी तथ्य कि 04.01.2002 को जब वह पर सात साल के थे, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो 'डीसीएलआर' गलत निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह प्रतिवादी नंबर 5 का 'बटाईदार' के प्रभाव से था।

14. विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि डी. सी. एल. आर. ने यह स्वीकार नहीं किया है कि उसकी मृत्यु के दिन, अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के पिता जो एक 'बटाईदार' भी थे, जिसके लिए वह तुरंत उत्तराधिकारी हो गया। उस पृष्ठभूमि में 'न्यायाधिकरण' ने प्रतिवादी सं.5 के मामले को सही तौर पर स्वीकार किया।

15. हम मामले के तथ्यों को देख चुके हैं और हमें प्रतिवादी नं.5 के रुख को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। 5 कि 'बटाईदारी' मुख्य रूप से रैयत और रैयत के तहत के बीच एक समझौता है जो तब तक चलता है जब तक कि 'बटाईदार' भूमि पर खेती कर रहा है और उक्त भूमि के लिए जमींदार को उपज-किराए का भुगतान नहीं करता है। 'बटाईदारी' अधिकार को तब तक विरासत में नहीं मिल सकता है, जब तक कि कोई रैयत के तहत 'अधिनियम' की धारा 48 डी के अर्थ के भीतर एक अधिभोग रैयत के अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते।

16. उस पृष्ठभूमि में, रैयत के तहत बनने के लिए, रैयत और रैयत के तहत अनुबंध का कुछ समझौता होना चाहिए और उसके अभाव में, प्रश्नगत आदेशों में हस्तक्षेप करना कठिन है।

17. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह नहीं पाया कि याचिकाकर्ता केवल एक वर्ष का था, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। न्यायाधिकरण ने जो पाया वह यह था कि 1980 में याचिकाकर्ता की आयु केवल एक वर्ष होगी और उसका यह दावा कि वह 1980 से अपने पिता के साथ भूमि पर खेती कर रहा था, गलत है। उनके पिता से उनकी विरासत को नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हालांकि वे 2002 में 24 साल के हो गए हैं (सीडब्ल्यूजेसी में आधार कार्ड के अनुसार डीओबी 01.01.1978 है), जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो रैयत के साथ कोई समझौता नहीं किया गया था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिता, जिनके तहत

याचिकाकर्ता दावा करता है, ने एक समान दावा किया था जिसे उचित प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था; इस प्रकार विरासत के उनके दावे को नकार दिया गया था।

18. उपायुक्त भूमि सुधार ने 'अधिनियम' के तहत आवश्यक मामले के गुण-दोष में गए बिना स्थानीय निरीक्षण के आधार पर आदेश पारित करने में स्पष्ट रूप से गलती की। कलेक्टर ने अपना बुद्धि लगाए बिना केवल 'डी. सी. एल. आर.' का तरीका लेकर अपील में भी गलती की।

19. जहाँ तक प्रश्नगत आदेशों का संबंध है, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

20. उस पृष्ठभूमि में, अपील खारिज कर दी जाती है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रॉय, न्यायाधीश)

किरन/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।